

International Relations

01 April
2022

1. वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022

चर्चा में क्यों?

- इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) ने बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022 लॉन्च किया।



प्रमुख बिंदु

वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022 के निष्कर्ष:

- वर्तमान ऊर्जा संकट को संबोधित करने वाले अल्पकालिक हस्तक्षेपों के साथ-साथ ऊर्जा ट्रांजिशन के मध्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- उच्च जीवाश्म ईंधन की कीमतें, ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं और जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता एक स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली में तेजी से आगे बढ़ने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- आउटलुक उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कार्यों को निर्धारित करता है जिन्हें 2030 तक महसूस किया जाना चाहिए ताकि मध्य शताब्दी तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जा सके।
- आउटलुक विद्युतीकरण और दक्षता को अक्षय ऊर्जा, हाइड्रोजन और टिकाऊ बायोमास द्वारा सक्षम ऊर्जा ट्रांजिशन के प्रमुख चालकों के रूप में देखता है।
- ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान और राष्ट्रीय ऊर्जा योजनाओं में बढ़ती महत्वाकांक्षा को निश्चितता प्रदान करनी चाहिए और 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप निवेश रणनीतियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

भारत के ऊर्जा ट्रांजिशन की स्थिति:

- 30 नवंबर 2021 को देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा (RE) क्षमता 150.54 गीगावॉट (सौर: 48.55 गीगावॉट, पवन: 40.03 गीगावॉट, लघु जल विद्युत: 4.83 गीगावॉट, जैव-शक्ति: 10.62 गीगावॉट, लार्ज हाइड्रो: 46.51 गीगावॉट) है, जबकि इसकी परमाणु क्षमता ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावॉट है।
- भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है।



संबंधित पहल/योजनाएं:

- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
- राष्ट्रीय सौर मिशन
- PM कुसुम
- सोलर पार्क योजना और ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018
- हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल वाहन

स्रोत: DTE

International Relations

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन 'ग्रह प्रवेशम' में भाग लेते हुए किया, जो उनके मालिकों को नए घर सौंपने के लिए एक समारोह है।



प्रमुख बिंदु

- देश में अब तक PMAY योजना के तहत 2.5 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ घर शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री ने लोगों से अगले 12 महीनों में देश के हर जिले में 75 'अमृत सरोवर' (तालाब) बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया, क्योंकि राष्ट्र अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है।



Daily Current Affairs

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण के बारे में:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण, पहले इंदिरा आवास योजना, भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है।
- शहरी गरीबों के लिए इसी तरह की एक योजना 2015 में 2022 तक सभी के लिए आवास के रूप में शुरू की गई थी।
- इंदिरा आवास योजना 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा गांवों में BPL आबादी के लिए घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में शुरू की गई थी।

स्रोत: ET

3. भारतीय ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए सुधारों की श्रृंखला

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने भारत के आगामी ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार उपाय किए हैं।



प्रमुख बिंदु

भारतीय ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए सुधार:

- उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021
- ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना
- UAS यातायात प्रबंधन (UTM) नीति फ्रेमवर्क
- कृषि ड्रोन की खरीद के लिए मौद्रिक अनुदान कार्यक्रम
- ड्रोन नियम, 2021 के तहत आवेदन फॉर्म DigitalSky प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन किए गए
- ड्रोन प्रमाणन योजना
- ड्रोन आयात नीति
- ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022

स्रोत: PIB



Daily Current Affairs

Important News: State

4. भारत सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय किया

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में **सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA)** के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय किया है।
- वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% की कमी आई है।



प्रमुख बिंदु

- संपूर्ण असम में वर्ष 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है। स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के कारण, अब 01.04.2022 से असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से AFSPA के प्रभाव से हटाया जा रहा है।
- संपूर्ण मणिपुर (इंफाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर) में अशांत क्षेत्र घोषणा वर्ष 2004 से चल रही है। 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को 01.04.2022 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर किया जा रहा है।
- सम्पूर्ण नागालैंड में अशान्त क्षेत्र अधिसूचना वर्ष 1995 से लागू है। नागालैंड में 01.04.2022 से 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया जा रहा है।

नोट:

- AFSPA के अंतर्गत अशांत क्षेत्र अधिसूचना को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में पूरी तरह से हटा लिया गया है।
- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 सुरक्षा बलों को कहीं भी कार्रवाई करने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस



5. सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई है।



प्रमुख बिंदु

- समय पर उपग्रह चेतावनी और रीयल-टाइम मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित अग्नि प्रतिक्रिया प्रणाली की उपलब्धता के बावजूद अकबरपुर रेंज में 8-10 वर्ग किमी क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में:

- सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले, राजस्थान, भारत में एक बाघ अभयारण्य है।
- यह 881 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें झाड़-झंखाड़ वाले शुष्क वन, शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और चट्टानी पहाड़ियाँ शामिल हैं।
- यह क्षेत्र अलवर राज्य का शिकारगाह था और 1958 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- 1978 में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाते हुए एक टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था।
- वन्यजीव अभयारण्य को 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 273.8 वर्ग किमी था।
- बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला यह दुनिया का पहला रिजर्व है।

राजस्थान के अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
- रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
- सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

नोट: हाल ही में, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति से राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य बनने की अनुमति मिली है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस



6. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए व्यापक नागरिक संपर्क मंच मायगॉव लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाने और "सुशासन" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **मायगॉव जम्मू-कश्मीर** लॉन्च किया। जम्मू-कश्मीर मायगॉव शुरू करने वाला देश का **पहला केंद्र शासित प्रदेश** है।



प्रमुख बिंदु

- मायगॉव जम्मू-कश्मीर मायगॉव की सात वर्षों से अधिक की यात्रा में 16वां मायगॉव इंस्टांस है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला मायगॉव इंस्टांस है।

मायगॉव के बारे में:

- भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में विचारों और मतों के स्वस्थ आदान-प्रदान के लिए एक इंटरफेस बनाकर सरकार को आम आदमी के करीब लाने के विचार के साथ, 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मायगॉव की शुरुआत की थी।
- सहभागी शासन के विचार को आगे बढ़ाते हुए, मायगॉव ने मायगॉव राज्य संस्करणों के कार्यान्वयन की शुरुआत की और 15 राज्यों - हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए सफलतापूर्वक इन्हें लागू किए हैं।

स्रोत: PIB

7. मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जुलाई 2024 तक चालू हो जाएगा

चर्चा में क्यों?

- BPX-इंदिरा डॉक पर बनकर तैयार होने वाला प्रतिष्ठित समुद्री क्रूज टर्मिनल - **मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल** के जुलाई 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

Mumbai International Cruise Terminal

- One of the best cruise terminals in India
- Capacity: 30 lakh Pax / 1000 ships per annum
- EPC Project - ₹10 Cr
- Operation and Maintenance on BPP Basis - ₹10 Cr
- EPC Project completion by 1st July 2024
- Operating by BPP operation by July 2024



Daily Current Affairs

- मुंबई पोत प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव जलोटा ने राष्ट्र के बंदरगाह-केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम - सागरमाला के 7 साल पूरे होने के अवसर पर यह जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- टर्मिनल में प्रति वर्ष 200 जहाजों और 1 मिलियन यात्रियों की आवाजाही को संभालने की क्षमता होगी।
- कुल परियोजना लागत 495 करोड़ रुपए में से 303 करोड़ रुपए मुंबई पोत प्राधिकरण और शेष निजी ऑपरेटरों द्वारा खर्च किए जाएंगे।

सागरमाला के बारे में:

- सागरमाला एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट और जलमार्ग की पूरी क्षमता को अनलॉक करके भारत के रसद क्षेत्र के निष्पादन में एक अगला कदम उठाना है।
- सागरमाला का दृष्टिकोण अनुकूलित बुनियादी ढांचा निवेश के साथ घरेलू और निर्यात-आयात कार्गो दोनों के लिए रसद लागत को कम करना है।

स्रोत: PIB

Important News: Defence

8. भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण - 2022 का 20वां संस्करण

चर्चा में क्यों?

- भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण- 'वरुण' 30 मार्च से 03 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है।



प्रमुख बिंदु

- दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी।
- इस अभ्यास को वर्ष 2001 में 'वरुण' नाम दिया गया था और यह भारत-फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।



- इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न टुकड़ियां भाग ले रही हैं।

स्रोत: इंडिया टुडे

Important News: Science

9. ISRO अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग क्षमता को तेज करेगा

चर्चा में क्यों?

- अंतरिक्ष मलबे के रूप में अंतरिक्ष में भारतीय संपत्ति के लिए एक बढ़ते खतरे के साथ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (नेत्रा) परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है।



प्रमुख बिंदु

- नेत्रा के तहत एक प्रभावी निगरानी और ट्रैकिंग नेटवर्क स्थापित करने के हिस्से के रूप में 1,500 किमी की दूरी के साथ एक अंतरिक्ष मलबे पर नज़र रखने वाले रडार और एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप को शामिल किया जाएगा।

अंतरिक्ष मलबा:

- अंतरिक्ष मलबे में प्रयोग किये गए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े और एंटी-सैटेलाइट सिस्टम (ASAT) से उत्पन्न मलबा शामिल होता है।
- लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 27,000 किमी प्रति घंटे की औसत गति से टकराती हुई ये वस्तुएँ अत्यधिक गंभीर खतरा पैदा करती हैं, क्योंकि इस टक्कर में सेंटीमीटर आकार के टुकड़े भी उपग्रहों के लिये घातक साबित हो सकते हैं।

नेत्रा परियोजना:

- यह भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।



Daily Current Affairs

- परिचालन के पश्चात् यह भारत को अन्य अंतरिक्ष शक्तियों की तरह स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (SSA) की क्षमता प्रदान करेगी।

नोट: वर्तमान में, भारत श्रीहरिकोटा रेंज (आंध्र प्रदेश) में एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का उपयोग करता है, लेकिन इसकी एक सीमित सीमा है।

स्रोत: द हिंदू

